(In crores of Rupees

Items	Years 1990-91	1991-92
1. Subsidy on fertilizers	4389.06	4799.60
2. Scheme of fertilizer subsidy to small and marginal farmers	..	385.44
3. Subsidy on Paper	5.22	..
4. Subsidy on sugar rice, wheat etc.	2450.00	2850.00

(b) and (c) There is no scheme to subsidise handloom weavers with regard to the price of yarn dyes and chemicals. The present fiscal position of government does not permit introduction of any subsidy scheme on the prices of these items. However, there are a number of existing Plan and non-Plan schemes for the development of the Handloom sector and weavers.

सांगली बैंक लिमिटेड के शेयरों में घांधली

2441. **डा० बापू कालदाते :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सांगली बैंक लिमिटेड, सांगली के शेयरों की खरीद में कुछ घांधली हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कलकत्ता में मित्तल ग्रुप ने इस बैंक को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बैंक को मित्तल ग्रुप के नियंत्रण से मुक्त कराने और इस बैंक के शेयर-धारकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, मित्तल समूह के बारे में प्राय: यह रिपोर्ट मिलती रही हैं कि वह नियंत्रक अधिकार प्राप्त करने के प्रयोजन से सांगली बैंक लि० के अधिकांश शेयर प्राप्त करने के प्रयास कर रहा है । सांगली बैंक लि० ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया है कि बैंक, शेयरधारकों, ग्राहकों और जनता के हितों पर विस्तार से समुचित विचार करने के बाद निदेशक बोर्ड के मित्तल समूह के पक्ष में शेयर अन्तरित करने से इंकार कर दिया है ।

Challiah Committee recommendation on rates of duty

4242. SHRI RAMSINH RATHWA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Challiah Committee have recommended to do away with specific rates of excise duty and depend more on advalorem or specific cum advalorem rate of duty;

(b) whether it is a fact that in accordance with the said recommendations Government have already started effecting the changes; if so, what are the details thereof;

(c) whether Government have found these recommendations proof;

(d) if so, by when the excise duty structure in all the industries will be rationalised as above; and

(e) if not in which specific industry the Government have found the recommendations unimplementable?